



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786  
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01  
अंक : 125  
दि. 07.02.2026,  
शनिवार  
पाना : 04  
किंमत : 00.50 पैसा

# नाबालिग की इच्छा सर्वोपरि, मातृत्व थोपना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

(जीएनएस)। नई दिल्ली/मुंबई। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बेहद संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला को, विशेषकर नाबालिग को, उसकी इच्छा के विरुद्ध मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक गरिमा हर महिला का मूल अधिकार है, जिसे कानून या नैतिक तर्कों के नाम पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह फैसला न केवल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी कानून की व्याख्या को व्यापक बनाता है, बल्कि समाज में महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों को लेकर एक सशक्त संदेश भी देता है।

जस्टिस जीवी नागरला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का दायित्व केवल भ्रूण की संभावित जीवित रहने की क्षमता तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि उसे उस लड़की की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा, जिसके शरीर में वह गर्भ पल रहा है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई नाबालिग लड़की गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती, तो उसका निर्णय सर्वोच्च प्राथमिकता का हकदार है, क्योंकि उस पर जबरन मातृत्व थोपना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले में यह प्रश्न गौण है कि गर्भ सहमति से बने संबंध का परिणाम है या यौन उत्पीड़न का। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीठिता



स्वयं नाबालिग है और वह इस अनचाहे गर्भ को आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। अदालत ने माना कि कानून का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है,

न कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में धकेल देना जहां वे जीवन भर के मानसिक आघात के साथ जीने को मजबूर हों। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रसव से किशोरी की जान

को तत्काल खतरा नहीं है और भ्रूण जीवित रहने की स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि केवल शारीरिक जोखिम की अनुपस्थिति किसी महिला की अनिच्छा को अनुरोध करने का आधार नहीं बन सकती। पीठ ने कहा कि मां की मानसिक स्थिति, उसकी उम्र और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों को अनदेखा करना न्याय की आत्मा के खिलाफ होगा। अदालत ने यह भी जोड़ा कि गरिमा और स्वायत्तता केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करना ही संवैधानिक मूल्यों की सच्ची परीक्षा है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि 30 सप्ताह का भ्रूण अब लगभग पूर्ण विकसित है और जन्म के बाद जीवित रह सकता है। सरकार ने सुझाव दिया कि किशोरी बच्चे को जन्म देकर उसे अनाथालय में सौंप सकती है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस नागरला ने कहा कि किसी लड़की से यह अपेक्षा करना कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण करे, प्रसव की पीड़ा सहें और फिर बच्चे को त्याग दे, मानवीय दृष्टि से भी स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने आगाह किया कि यदि ऐसे मामलों में कानून और न्याय व्यवस्था कठोर रुख अपनाती है, तो महिलाएं और नाबालिग मजबूर असुरक्षित और अवैध गर्भपात के रास्ते चुनेंगी, जो उनके जीवन और स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के

जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में तुरंत गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करे और यह सुनिश्चित करे कि किशोरी को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरा सहयोग मिले। अदालत ने गर्भपात से जुड़े समयबद्ध कानूनी प्रतिबंधों पर भी गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि जब कानून विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है, तो आसधारण हालात में 30 सप्ताह पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। अदालत ने स्वीकार किया कि किसी संभावित जीवन को समाप्त करने का निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन किसी लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ मातृत्व थोप देना उससे कहीं अधिक अन्यायपूर्ण है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय समाज को यह संदेश देता है कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा को रक्षा भी है। अदालत ने स्वीकार किया कि रक्षा भी है। लड़की पर उसकी मर्जी के खिलाफ मातृत्व थोप देना उससे कहीं अधिक अन्यायपूर्ण है। इस फैसले को महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र में एक मील का

## हिंसा से तौबा की राह पर विद्रोह, ओडिशा में इनामी माओवादियों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण

(जीएनएस)। रायगड़ा। दशकों से बंदूक और बारूद के साप में जी रहे माओवादी आंदोलन के भीतर एक बड़ी दरार उस वक्त साफ दिखाई दी, जब ओडिशा में एक दंपति सहित 19 माओवादियों ने सामूहिक रूप से हथियार डालकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन विद्रोहियों पर कुल मिलाकर करीब एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि माओवादी हिंसा का आकर्षण अब तेजी से खत्म हो रहा है और संगठन के भीतर मोहभंग गहराता जा रहा है। ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाई. बी. खुराना ने रायगड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में निरंजन राउत उर्फ निखिल और उनकी पत्नी रश्मिना लोका उर्फ इंदु प्रमुख हैं। दोनों माओवादी संगठन की राज्य समिति के सदस्य थे, जो केन्द्रीय समिति के बाद संगठन का दूसरा सबसे ऊंचा और प्रभावशाली पद माना जाता है। निरंजन और रश्मिना पर अलग-अलग मामलों में कुल



55.10 लाख रुपये का इनाम घोषित था। लंबे समय तक संगठन की रणनीति, भर्ती और हिंसक गतिविधियों में सक्रिय रहने के बाद इस दंपति का सरेंडर करना माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस आत्मसमर्पण की प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे लंबा संवाद और आत्ममंथन रहा। कुछ समय पहले ही निरंजन और रश्मिना ने ओडिशा सरकार को पत्र लिखकर हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने भरोसे

का माहौल बनाया और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन दिया। अंततः यह संवाद हथियार डालने और खुले तौर पर आत्मसमर्पण के रूप में सामने आया। इस समूह में शामिल 13 माओवादियों ने रायगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया, जबकि चार अन्य सदस्यों ने कंधमाल जिले में हिंसा छोड़ने की घोषणा की। सरेंडर करने वालों ने अपने पास मौजूद हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण भी पुलिस को सौंप दिए। अधिकारियों का कहना है कि इनमें ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अतीत में सुरक्षा बलों पर हमलों और विकास कार्यों को बाधित करने में किया गया था। डीजीपी खुराना ने इस मौके पर कहा कि

ओडिशा में माओवादी गतिविधियां अब अंतिम चरण में हैं। उन्होंने बताया कि लगातार चलाए गए सुरक्षा अभियानों, विकास योजनाओं और आत्मसमर्पण नीति के कारण राज्य में माओवादियों की संख्या बेहद कम रह गई है। जिन इलाकों में कभी पुलिस और प्रशासन का पहुंचना मुश्किल माना जाता था, वहां अब सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल नेटवर्क पहुंच चुका है। यही वजह है कि माओवादी संगठन का आधार कमजोर हुआ है और उसके कैडर भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने भी अनौपचारिक बातचीत में स्वीकार किया कि जंगलों में जीवन बेहद कठिन और असुरक्षित हो चुका था। लगातार मुठभेड़ों का डर, संसाधनों की कमी और संगठन के भीतर बढ़ती अविश्वास उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। कई लोगों ने यह भी कहा कि आदिवासियों के अधिकार और विकास के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुका है और आम ग्रामीणों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

## जुमे की नमाज़ में लहलुहान हुई इबादत इस्लामाबाद में दहशत का साया

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी शुक़रवार दोपहर उस समय दहशत और मातम में डूब गई, जब जुमे की नमाज़ के दौरान एक शिया इमाम बाराह में जोरदार धमाका हो गया। तरलाई इलाके में स्थित इमाम बाराह खदीज़त-उल-कुबरा में हुए इस आत्मघाती हमले ने नमाज़ में जुटे सैकड़ों लोगों की खुशियों और सुकून को पल भर में खून और चीबों में बदल दिया। धमाके में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 169 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया।



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही नमाज़ अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी, उसी दौरान इमाम बाराह के मुख्य द्वार के पास और बाहर का मंजर बेहद भयावह हो गया। धमाके के तुरंत बाद इमाम बाराह के भीतर अचानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज़ दूर-दराज के इलाकों तक सुनाई दी और मस्जिद के भीतर अफ़रा-तफ़री मच गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर को सुरक्षा कर्मियों ने

खून से सनी चटईयां और टूटे-फूटे सामान बिखरे पड़े थे। जान बचाने के लिए लोग धड़-उधर भागते दिखे, जबकि कुछ लोग घायलों को उठाकर

सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने की कोशिश करते रहे। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें इमाम बाराह के फ़र्श पर बेसुध पड़े लोग और मदद के लिए पुकारते दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया। बम निरोधक दस्ते और फ़ॉरेंसिक टीमें को भी तुरंत बुलाया गया, ताकि धमाके की प्रकृति और इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के बारे में जांच की जा

## मैक-8 की रफ़्तार से भारत की ताकत का प्रदर्शन: चांदीपुर से अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

(जीएनएस)। चांदीपुर। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करते हुए शुक़रवार, 6 फरवरी को इंटरमीडियट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरवीएम) अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया, जहां से स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने तय मानकों के अनुरूप सटीक उड़ान भरी और अपने लक्ष्य को पूरी तरह सफलतापूर्वक साधा। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस टेस्ट में अग्नि-3 की सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल क्षमताएं पूरी तरह खरा उठीं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि-3 को भारत की सबसे घातक और भरोसेमंद मिसाइलों में गिना जाता है। इसके सफल परीक्षण को भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस यानी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिहाज से एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। यह मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत का ऐसा मजबूत स्तंभ है, जो किसी भी संभावित खतरे का करारा जवाब देने में सक्षम है। अग्नि-3 की मारक क्षमता इतनी व्यापक है कि पाकिस्तान का लगभग पूरा क्षेत्र इसकी जद में आता है, वहीं चीन के भी कई बड़े और अहम शहर इसकी रेंज में माने जाते हैं। इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अग्नि-3 एक दो-चरणीय टोप ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यह मिसाइल परमाणु और पारंपरिक, दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिससे इसकी रणनीतिक उपयोगिता

और भी बढ़ जाती है। इसकी अधिकतम रेंज 3000 से 3200 किलोमीटर की दूरी तक लिए जा चुके हैं। करीब 17 मीटर लंबी और लगभग 48 से 50 टन वजन यह मिसाइल मैक-7 से मैक-8 की अत्यधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इतनी तेज रफ़्तार के कारण दुश्मन की किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही इसकी सटीकता भी इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। बताया जाता है कि अग्नि-3 का सफल परीक्षण प्रोबेबल यानी सीईपी 40 मीटर से भी कम है, जो इसे अत्यंत सटीक हथियार बनाता है। अग्नि-3 का पहला परीक्षण वर्ष 2006 में किया गया था। इसके बाद से यह मिसाइल कई बार सफलतापूर्वक टेस्ट की जा चुकी है और हर बार इसने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। भले ही अग्नि-4 और अग्नि-5 के मुकाबले इसकी रेंज कुछ कम मानी जाती हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसकी भूमिका आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह मिसाइल भारत की न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक नीति का एक मजबूत आधार है। इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी मिसाइल तकनीक पूरी तरह परिपक्व, भरोसेमंद और किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशनल है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर यह उपलब्धि न केवल देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सामरिक स्थिति को भी सशक्त बनाती है।

## सफाईकर्मों से मेयर तक का सफर: छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने अशोक हिरवाले को उतारा मैदान में

(जीएनएस)। छत्रपति संभाजीनगर। नगर निगम की राजनीति में एक प्रतीकात्मक और सामाजिक संदेश देने वाला कदम उठाते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर पद के लिए एक सफाईकर्मों से पार्श्व बने अशोक हिरवाले को उम्मीदवार घोषित किया है। शुक़रवार को इस घोषणा के साथ ही नगर निगम की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने न केवल अपना उम्मीदवार उतारा, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे अनुसूचित जातियों के प्रति अपने कथित समर्थन को साबित करते हुए अशोक हिरवाले के पक्ष में एकजुट हों। 15 नवंबर को हुए 115 सदस्यीय छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद एआईएमआईएम ने 33 सीटों के एक राउंड उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मात्र 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को छह और वंचित बहुजन अघाड़ी को चार सीटें मिलीं। इस बीच भाजपा और शिंदे की शिवसेना ने मिलकर मेयर पद के लिए समीर राजुकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मेयर पद के लिए चुनाव 10 फरवरी को होंगे हैं। एआईएमआईएम महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि पार्टी ने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को मेयर पद के लिए नामांकित किया है, जिसने जीवन का बड़ा हिस्सा नगर निगम की

सफाई व्यवस्था में काम करते हुए बिताया है। उन्होंने बताया कि अशोक हिरवाले ने करीब 28 वर्षों तक नगर निगम में सफाईकर्मों के रूप में सेवा दी और बाद में पार्श्व बने। जलील ने इसे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना (यूबीटी), वंचित बहुजन अघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आती हैं, तो कुल संख्या 58 हो जाती है, जो भाजपा के 57 पार्श्वों से अधिक है। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक मेयर चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करने का अवसर है कि क्या राजनीतिक दल वास्तव में वंचित और अनुसूचित समाज के लोगों को नेतृत्व में देखना चाहते हैं या नहीं। इस नामांकन को नगर की राजनीति में सामाजिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ओर भाजपा और शिंदे गुट का शिवसेना सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम इस चुनाव को सामाजिक संदेश देने वाले मंच के रूप में प्रस्तुत कर रही है। अशोक हिरवाले की उम्मीदवारी ने सफाईकर्मियों और दलित समुदाय में खास चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब इतने लंबे समय तक सफाईकर्मों के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को सीधे मेयर पद के लिए उतारा गया है।



नवसर्जन संस्कृति  
हिन्दी



JioTV  
CHENNAL NO. 2063



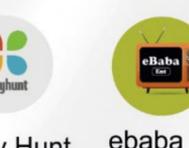
Jio Air Fiber



Jio tv+



Jio Fiber



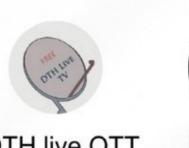
Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



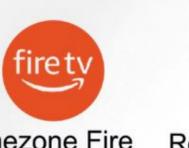
DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Roku Tv-US.UK

### देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

## संपादकीय

### पंजाब के प्राकृतिक

## सुरक्षा कवच पर चोट

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के होसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बतलाता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कहीं जाएगी कि इस बावत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों को तमाम दलीलों खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वक्तु-स्थिति से अवागत होने के बावजूद इन आपराधिक कार्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े देवदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अक्सर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती। वास्तव में अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्रों का सख्त सीमांकन, प्रौद्योगिकी का आधारित निगरानी तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।

## अभियान

# नारायण का कवच: जब भक्ति स्वयं बन जाए रक्षा-सूत्र

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कुछ मंत्र, स्तोत्र और कवच ऐसे हैं जो केवल शक्ति बंद नहीं रहते, बल्कि साधक के जीवन में जीवंत शक्ति बनकर उतर आते हैं। नारायण कवच उसी श्रेणी का दिव्य विधान है, जहाँ भक्ति, समर्पण और ईश्वरीय संरक्षण एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह कवच किसी युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन के हर युद्ध में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की साधना है। जब मनुष्य अपने चारों ओर असुरक्षा, भय, अनिश्चितता और अदृश्य संकटों का अनुभव करता है, तब नारायण कवच उस वृहत् स्मरण करता है कि वह अकेला नहीं है, स्वयं नारायण उसके अंग-अंग में प्रतिष्ठित हैं।

नारायण कवच का मूल भाव पूर्ण शरणगति है। यह उस अस्पष्टता की ओर ले जाता है जहाँ साधक अपने अहंकार, भय और सीमित सोच को त्यागकर स्वयं को परम सत्ता के हाथों सौंप देता है। श्रीमद्भागवत पुराण के छठे स्कंध में वर्णित यह कवच केवल इंद्र की विजय कथा तक सीमित नहीं

है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों में भीतर से टूटता हुआ अजीब को संभालना चाहता है। जब देवराज इंद्र असुरों के आतंक से भयभीत होकर अपनी शक्ति खो बैठे थे, तब विश्वरूप ऋषि ने उन्हें यह कवच प्रदान किया। यह घटना हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर-स्मरण और भक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता।

भक्ति का मार्ग तर्क से नहीं, अनुभूति से खुलता है। नारायण कवच का पाठ करते समय जब साधक श्लोकों का उच्चारण करता है, तब वह केवल ध्वनि नहीं निकालता, बल्कि अपना भीतर ईश्वर को आमंत्रित करता है। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान विष्णु के विभिन्न रूप साधक के शरीर और चेतना में प्रतिष्ठित होते जाते हैं। यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई भक्त अपने हृदय में दीप जलाता जाए और अंधकार स्वयं हटता चला जाए। धीरे-धीरे साधक को लगने लगता है कि उसके चारों ओर एक अदृश्य आलोक फैल गया है, जिसमें भय,

शंका और नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। नारायण कवच की भक्ति-शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह साधक को निर्भय बनाता है। यहाँ निर्भयता का अर्थ अहंकार से भरा साहस नहीं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास से उपजा आत्मबल है। जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि उसके जीवन का संचालन नारायण की इच्छा से हो रहा है, तब वह हर परिस्थिति को प्रसाद भाव से स्वीकार करने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ कवच बाहरी नहीं, भीतरी बन जाता है। शरीर की रक्षा से अधिक यह मन और आत्मा की रक्षा करता है। मकर संक्रांति जैसे पुण्य काल में नारायण कवच का पाठ भक्ति को और गहरा बना देता है। उत्तरायण का समय भारतीय परंपरा में चेतना के जागरण का प्रतीक माना गया है। सूर्य का उतर की ओर गमन केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। ऐसे समय में जब साधक नारायण कवच का पाठ करता है, तो वह स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय

में पाता है। यह अनुभव ऐसा होता है मानो भक्त की प्रार्थना सीधे ईश्वर के श्रोतों तक पहुँच रही हो। भक्ति का स्वरूप यहाँ कर्मकांड तक सीमित नहीं रहता। नारायण कवच साधक को एक जीवन-दृष्टि प्रदान करता है। वह सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईश्वर-विश्वास से आती है। आज के समय में जब मनुष्य आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भीतर से असुरक्षित महसूस करता है, तब यह कवच उसे याद दिलाता है कि नारायण सदा उसके साथ हैं। यह स्मरण ही सबसे बड़ा कवच है।

कवच के श्लोकों में भगवान के विविध अवतारों का आह्वान एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये सभी रूप साधक को यह अनुभव कराते हैं कि ईश्वर हर युग, हर परिस्थिति और हर संकट में उपस्थित हैं। जब भक्त इन नामों का स्मरण करता है, तो उसे लगता है कि

उसका जीवन भी किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। इस भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति संकट में भी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक निश्चला है। नारायण कवच का पाठ धीरे-धीरे साधक के स्वभाव में परिवर्तन लाता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और चिंता जैसी सच्ची सुरक्षा बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईश्वर-विश्वास से आती है। आज के समय में जब मनुष्य आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भीतर से असुरक्षित महसूस करता है, तब यह कवच उसे याद दिलाता है कि नारायण सदा उसके साथ हैं। यह स्मरण ही सबसे बड़ा कवच है।

कवच के श्लोकों में भगवान के विविध अवतारों का आह्वान एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि—ये सभी रूप साधक को यह अनुभव कराते हैं कि ईश्वर हर युग, हर परिस्थिति और हर संकट में उपस्थित हैं। जब भक्त इन नामों का स्मरण करता है, तो उसे लगता है कि

है कि जो इस कवच को धारण करता है, उसके लिए दिशाएँ भी भयमुक्त हो जाती हैं। आज के अनिश्चित और भागदौड़ भरे जीवन में नारायण कवच एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल जैसा है। यहाँ आकर मनुष्य अपने बुरे उतार-चढ़ाव में, अपने प्रश्न छोड़ सकता है और बस इतना कह सकता है—“हे नारायण, अब तुम संभालो।” जब सम्पूर्ण भक्ति की पराकाष्ठा है। यही भक्त इस भाव में स्थिर हो जाता है, तब संसार की कोई भी बाधा उसे भीतर से विचलित नहीं कर पाती।

अंततः नारायण कवच हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की रक्षा कोई बाहरी दीवार नहीं, बल्कि भीतर जलता हुआ विश्वास का दीप है। यह दीप जितना उज्वल होगा, अंधकार स्मरण करते हुए जीया गया जीवन स्वयं एक कवच बन जाता है—अभेद्य, शांत और दिव्य। जब भक्त यह अनुभव कर लेता है, तब उसके लिए हर दिन संक्रांति है और हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ।

# तंग नजरिये से छोटान हो भारतीयता का आंगन



## देश के हर

### विवेकशील नागरिक

### के मन में यह सवाल

### उठना चाहिए।

### भारतीयता के आंगन

### में धर्म की दीवारें

### खड़ी करने वालों

### को यह बात क्यों

### समझ नहीं आ रही

### कि ऐसी हर दीवार

### आंगन को छोटा

### ही करती है। आज

### अपने आंगन को

### बांटना नहीं है, पूरे

### आंगन में धूप की

### ऊष्मा और रोशनी

### पहुंचाना हमारी

### आवश्यकता है।

## प्रेरणा



# जब संवेदना की कोई सरहद नहीं होती

साहित्य की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो किसी एक देश, भाषा या कालखंड तक सीमित नहीं रहते। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरी मानवता की चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही एक लेखक थे रूसी उपन्यासकार मैक्सिम गोर्की। उनका लेखन सत्ता के केंद्रों के आसपास नहीं घूमता था, बल्कि समाज के उस वर्ग के इर्द-गिर्द था, जिसे अक्सर इतिहास और व्यवस्था हाशिए पर छोड़ देती है। मजदूर, किसान, गरीब, शोषित और संवेदना-वर्धन—गोर्की की लेखनी का असली केंद्र यही लोग थे। 'मा' जैसा उपन्यास लिखकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि साहित्य केवल मनोरंजन या सौंदर्यबोध का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवीय चेतना का शक्तिशाली स्रोत भी हो सकता है।

भारत में हिंदी साहित्य के महान कथकार मुंशी प्रेमचंद भी उसी परंपरा के लेखक थे। उनके लिए साहित्य का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करना था। प्रेमचंद किसानों की बदहाली, मजदूरों की पीड़ा, स्त्रियों की विवशता और सामाजिक अन्याय को जिस संवेदनशीलता से लिखते हैं, वही उन्हें साधारण कथाकार से अलग करता है। यही वैचारिक समानता थी, जिसने प्रेमचंद को मैक्सिम गोर्की के प्रति गहरा सम्मान और आपाजप महसूस कराया। वे गोर्की को केवल एक विदेशी लेखक के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे सृजक के रूप में देखते थे, जो आम आदमी के जीवन को समझता था और उसके लिए लिखता था।

जून 1936 का वह समय प्रेमचंद के जीवन का

अत्यंत कठिन दौर था। वे स्वयं तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। शरीर दुबल था, लगातार खाँसी और थकावट उन्हें रूहे रहती थी, लेकिन मन और चेतना पूरी तरह सज्ज थी। इसी दौरान जब उन्हें यह समाचार मिला कि मैक्सिम गोर्की का निधन हो गया है, तो वे भीतर तक व्यथित हो उठे। यह केवल किसी प्रसिद्ध लेखक की मृत्यु की सूचना नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक साथी, एक प्रेरणा और एक आदर्श के चले जाने का दुःख था। बीमारी और कमजोरी के बावजूद उस रात प्रेमचंद सो नहीं सके। वे रात भर जागते रहे और गोर्की के सम्मान में एक शोक-प्रस्ताव लिखते रहे, जिसे शोक-सभा में पढ़ा जाया था। पत्नी शिवरानी देवी ने जब यह दृश्य देखा, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि गोर्की तो हिंदुस्तान के नहीं थे, फिर इतनी बेचैनी क्यों? यह प्रश्न सामान्य दृष्टि से बिल्कुल उचित था, लेकिन प्रेमचंद का उत्तर उनकी साहित्यिक और मानवीय दृष्टि को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि जो लेखक आम आदमी के सुख-दुःख से सरोकार रखता है और उसके लिए लिखता है, वह किसी एक देश का नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया का होता है। ऐसे लेखक को 'परम्या' कहना ही गलत है। इसलिए गोर्की उनके लिए 'अपने' थे, और अपने व्यक्ति के लिए शोक-प्रस्ताव लिखना तो एक नैतिक कर्तव्य था। इस उतर में प्रेमचंद की पूरी साहित्यिक उदारता स्पष्ट हुई थी। उनके लिए राष्ट्र, भाषा और भौगोलिक सीमाएँ मानवीय संवेदना से छोटी थीं। वे यह मानते थे कि सच्चा साहित्यकार वह होता है, जो मनुष्य की पीड़ा को समझे, उसके संघर्ष को स्वर दे और



की मांग करता है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया और इस साहस के लिए देश के विवेकशील नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विवेकशील लोगों की कमी नहीं है देश में, पर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय के लिए खतरा मोल लेना भी कोई आसान काम नहीं है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया है। ऐसे हर दीपक का हीसला बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस दिन अखबार में 'मोहम्मद दीपक कुमार' की यह खबर छपी थी, उसी दिन एक खबर देश की पूर्वी सीमा से भी आयी थी। असम की बात है यह। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का एक बयान छपा था अखबारों में। वह कह रहे थे कि मुसलमान रिश्ता चालक को हिंदुओं से कम महँनताना देना चाहिए। कोई भी यदि इस तरह के भेदभाव वाली बात कहे तो उसे गलत ही कहा जायेगा। पर यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है तो उसकी सोच पर गुस्सा ही नही आता, तरस भी आता है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति

यदि इस तरह की घटिया सोच का प्रदर्शन करता है तो बात और भी गंभीर हो जाती है। यह दुर्भाग्य ही है कि आजादी अर्जित करने के इतने साल बाद इस तरह की सोच के उदाहरण सामने आ रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों ने देश के संविधान में पंथ-निरपेक्ष भारत की व्यवस्था की थी तो यह निर्णय बहुत सोच-विचार कर लिया गया था। यह सही है कि देश का बँटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, पर हमारे तत्कालीन नेताओं ने कभी यह नहीं स्वीकारा कि हमारा भारत किसी एक धर्म को मानने वालों का देश बन जाये। दुनिया में शायद ही कोई और देश होगा जहाँ इतने धर्मों को मानने वाले लोग हों जितने हमारे देश में हैं। भारत ने हर धर्म का स्वागत किया है। हमारी बहुधर्मिता हमारी ताकत है। यह सही है कि भारत में लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी हिंदू है, लेकिन यहाँ हर धर्म को मानने वालों को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। ऐसे में जब धर्म के आधार पर भेदभाव करने का

कोई उदाहरण सामने आता है, और यदि उदाहरण मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो हैरानी भी होती है, और पीड़ा भी।

कुछ ऐसा ही एक उदाहरण पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्तुत किया है। 'सबका साथ, सबका विकास' हमारे प्रधानमंत्री का प्रिय नारा है। वे और उनकी पार्टी के अन्य नेता इस बात का दावा भी करते हैं कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेद-भाव के हर धर्म को मानने वाले के विकास की चिंता करती हैं। होना भी यही चाहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने दल का ही नेता नहीं होता, सारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह। इसलिए, जब सबके साथ और सबके विकास की बात होती है तो उसका अर्थ स्वागत ही होना चाहिए। पर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु खुलेआम यह कह रहे हैं कि इस नीति को बदला जाना चाहिए। हाल ही में उन्होंने यह कहा है कि 'अब' यह नीति नहीं चलेगी। उन्होंने घोषणा की है कि 'जो हमारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं'। स्पष्ट है, वे अपने राजनीतिक विरोधियों की ही नहीं, गैर हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं। जातव्य है कि कुछ अर्सा बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उसके कुछ बाद असम में चुनाव की बारी है। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव की आशंकाएँ मंडरा रही हैं। सवाल सिर्फ चुनाव में हार-जीत का नहीं है, सवाल उस बीमार सोच का है जिसके चलते देश की जनता को धर्म के आधार पर बाँटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही किसी भी सोच के अंतर्गत 'बढ़ते तो बढ़ते' की चेतावनी दी हो, पर यह चेतावनी सारे देश के लिए है हमने अपने संविधान में हर भारतीय को समता, न्याय और बंधुता के आधार पर समान अधिकार देते ही व्यवस्था की थी।

ऐसे में जब कोई शुभेंदु अधिकारी चुनावी सभा में श्रोताओं को इस आशय की धमकी देता है कि 'सड़क तब मिलेगी जब तुम धर्म बदलोगे', तो हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है।

ऐसा ही गुस्सा कोटद्वार के दीपक को आया होगा जब उसने यह देखा कि 75 साल के एक मुसलमान व्यापारी को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उसकी दुकान के नाम में 'बाबा' जुड़ा हुआ है। तीस साल से चल रही है यह दुकान। तीस साल तक किसी को इस पर कोई विचार नहीं हुई। तो, आज यह विवाद किसलिए? यह सवाल सिर्फ 'मोहम्मद दीपक' नाम वाले युवक का नहीं है। देश के हर विवेकशील नागरिक के मन में यह सवाल उठना चाहिए। भारतीयता के आंगन में धर्म की दीवारें खड़ी करने वालों को यह बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ऐसी हर दीवारें आंगन को छोटा ही करती है। आज अपने आंगन को बांटना नहीं है, पूरे आंगन में धूप की ऊष्मा और रोशनी पहुंचाना हमारी आवश्यकता है। जिस साहस और समझदारी के साथ 'मोहम्मद दीपक कुमार' ने धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाने वालों का सामना किया है, आज देश के हर युवा में उस साहस और समझदारी की आवश्यकता है।

कोटद्वार में जो कुछ हुआ उसका एक हिस्सा यह भी है कि यह घटना इसी 26 जनवरी की, अर्थात् जब सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब घटी थी। यह वह दिन है जब हमने धर्म-निरपेक्ष भारत के लिए एक संविधान को अंगीकृत किया था। हर 26 जनवरी को हम उस संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। हमारे नेता समता और न्याय के पक्ष में खड़े होना क्यों जरूरी नहीं समझते? मोहम्मद दीपक ने यह बात समता, न्याय और बंधुता के आधार पर समान अधिकार देते ही व्यवस्था की थी।

## Dragon की सेना में आई दरार, अपने ही जनरल बन रहे खतरा, अपनी सत्ता

### बचाने की जंग लड़ रहे Xi Jinping

मार्च 2023 में जब चीन की सेना का शीपिंग नेतृत्व राष्ट्र के सामने एकदुःखी दिखाया गया, तब संदेश साफ था कि शी जिनिपिंग ने लगभग एक दशक की सत्ता के बाद अपनी पसंद का सैन्य ढांचा खड़ा कर लिया है। अपने भरोसे के अधिकारियों को ऊपर बैठकर उन्होंने जन मुक्ति सेना को विश्व स्तर की शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा था। पर अब वही ढांचा भीतर से हिलता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के नाम पर चल रही कार्रवाई ने सेना के सबसे ऊंचे हलकों को झकझोर दिया है। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य एक एक हटाए जा रहे हैं या जर्ज के घेरे में आ रहे हैं। ताजा और सबसे चौंकाने वाला मामला शी जिनिपिंग के करीबी माने जाने वाले शीपिंग सेनापति झांग योउश्या का है। उनके साथ एक और प्रमुख कमान संभालने वाले अधिकारी लियू झेनली भी पद से हटाए गए हैं।

साल 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम तीस ऐसे जनरल और एडमिरल स्तर के अधिकारी थे जो विशेष विभागों और क्षेत्रीय कमानों का संचालन कर रहे थे। अब इनमें से लगभग सभी या तो बाहर कर दिए गए हैं या सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। उनकी जगह लगाए गए कई नए अधिकारी भी ज्यादा समय तक नहीं टिके। सक्रिय भूमिका में बचे अधिकारियों की संख्या बेहद कम बताई जा रही है।

शी जिनिपिंग की इस कार्रवाई से सेना में नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ है। झांग योउश्या और लियू झेनली जैसे अधिकारी की तैयारी और संचालन की योजना में अहम माने जाते थे। उनके अचानक हटने से जन मुक्ति सेना की तैयारी और भरोसे पर असर पड़ना स्वाभाविक है। केंद्रीय सैन्य आयोग में अब जो प्रमुख चेहरा बचा है वह झांग शेंगमिन हैं, जिनकी पहचान राजनीतिक अनुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी जांच से जुड़ी रही है। उन्होंने प्रक्षेपास्त्र बल में लंबा समय अनुशासन अधिकारी के रूप में बिताया। यही बल चीन के परमाणु और पारंपरिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम संभालता है। पिछले वर्ष उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था।

हम आपको यह भी बता दें कि कार्रवाई केवल थल सेना तक सीमित नहीं रही है। नौसेना, प्रक्षेपास्त्र बल और लगभग सभी शाखाओं में यह कार्रवाई चली है। साथ ही पांचों क्षेत्रीय कमान, जिन्हें 2016 में नई संरचना के तहत बनाया गया था, भी इससे अछूती नहीं रही। पूर्वी क्षेत्रीय कमान, जो ताइवान के आसपास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और हाल में नया कमांडर लगाया गया है।

इसका सामरिक असर भी गहरा है। सेना किसी भी देश की ताकत का आधार होती है। जब शीपिंग कमान बार बार बदले, जब अधिकारियों को हर समय डर रहे कि अगली बारी उनकी है, तब साहसी और अछूती नहीं रही। पूर्वी क्षेत्रीय कमान, जो ताइवान के आसपास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और हाल में नया कमांडर लगाया गया है।

और जवानों से अपील की है कि वे फैसलों का समर्थन करें और शी जिनिपिंग के साथ खड़े रहें। साथ ही यह भी माना गया कि इन कर्मों से अल्प अवधि की कटिबद्ध और पीड़ा हो रही है मगर दावा किया गया है कि अंत में सेना और मजबूत बनकर उभरेगी।

इसी बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े तीन संसदों को भी उनके पद से हटा दिया गया है। वे लोग रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष उड़ान और परमाणु उद्योग से जुड़े थे। इनमें एक बड़ी सरकारी विमान निर्माण कंपनी के पूर्व प्रमुख, एक लंबे समय से परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक और एक सरकारी परमाणु उर्जा कंपनी के मुख्य अभियंता शामिल हैं। कारण सांख्यिक नहीं किए गए, पर यह कदम संसद के वार्षिक अधिवेशन से ठीक पहले उठाया गया।

चीन ने 2035 तक पूर्ण सैन्य आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है। पर सेना के भीतर भ्रष्टाचार को इस राह में बाधा माना जा रहा है। कुछ हटाए गए अधिकारियों के नाम उनकी संस्थाओं की सूची से भी गायब कर दिए गए हैं। साथ ही कई रक्षा कर्मियों में भ्रष्टाचार विरोधी बैठकें तेज कर दी गई हैं।

वहीं सबसे गंभीर आरोप यह है कि शीपिंग सेनापति झांग योउश्या पर परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी अमेरिका तक तक नहीं टिके। सक्रिय भूमिका में बचे अधिकारियों की संख्या बेहद कम बताई जा रही है। शी जिनिपिंग की इस कार्रवाई से सेना में नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ है। झांग योउश्या और लियू झेनली जैसे अधिकारी की तैयारी और संचालन की योजना में अहम माने जाते थे। उनके अचानक हटने से जन मुक्ति सेना की तैयारी और भरोसे पर असर पड़ना स्वाभाविक है। केंद्रीय सैन्य आयोग में अब जो प्रमुख चेहरा बचा है वह झांग शेंगमिन हैं, जिनकी पहचान राजनीतिक अनुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी जांच से जुड़ी रही है। उन्होंने प्रक्षेपास्त्र बल में लंबा समय अनुशासन अधिकारी के रूप में बिताया। यही बल चीन के परमाणु और पारंपरिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम संभालता है। पिछले वर्ष उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था।

हम आपको यह भी बता दें कि कार्रवाई केवल थल सेना तक सीमित नहीं रही है। नौसेना, प्रक्षेपास्त्र बल और लगभग सभी शाखाओं में यह कार्रवाई चली है। साथ ही पांचों क्षेत्रीय कमान, जिन्हें 2016 में नई संरचना के तहत बनाया गया था, भी इससे अछूती नहीं रही। पूर्वी क्षेत्रीय कमान, जो ताइवान के आसपास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और हाल में नया कमांडर लगाया गया है।

इसका सामरिक असर भी गहरा है। सेना किसी भी देश की ताकत का आधार होती है। जब शीपिंग कमान बार बार बदले, जब अधिकारियों को हर समय डर रहे कि अगली बारी उनकी है, तब साहसी और अछूती नहीं रही। पूर्वी क्षेत्रीय कमान, जो ताइवान के आसपास की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, वहां भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं और हाल में नया कमांडर लगाया गया है।



# मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के सुघड स्थित आनंद निकेतन स्कूल में 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण में सहभागी हुए

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रेरणात्मक संदेश बच्चों ने आत्मसात किया  
▶▶ परीक्षा आपकी मेहनत का प्रतिबिंब है तथा तनाव को सफलता में बदलने का प्लेटफॉर्म है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल  
▶▶ विद्यार्थी अभ्यास और पठन के टाइम टेबल की तरह मोबाइल टीवी देखने का भी समय तय करें : मुख्यमंत्री का बच्चों से अनुरोध  
▶▶ डिप्रेशन में आए बिना जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी परिस्थिति का स्वस्थ मन से सामना करने की मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की बच्चों को सीख

(जीएनएस)। गांधीनगर, : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर मौजूद डर और असफलता का भय दूर करने की प्रेरणा देने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' देशभर में शुरू करवाया है। प्रधानमंत्री पिछले 8 वर्षों से विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं सहित वार्षिक परीक्षाओं से पहले इस उपक्रम में 'परीक्षा पे चर्चा' का गहन मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष शुरुआत को 'परीक्षा पे चर्चा' के नौवें संस्करण में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के सुघड स्थित आनंद निकेतन स्कूल के छात्रों के साथ सहभागी हुए।  
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, विधायक श्री अल्पेशभाई ठाकोर, जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. आशीष देवे

तथा कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत का प्रतिबिंब है और तनाव को सफलता में बदलने का प्लेटफॉर्म है। उन्होंने डिप्रेशन में आए बिना जीवन का संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ मन से आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्तमान समय में विद्यार्थियों में बड़ रही मोबाइल फोन की लत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे बच्चे पढ़ाई, अध्ययन और खेल कूद का समय तथा टाइम टेबल तय करते हैं, वैसे ही मोबाइल देखने का भी निश्चित समय तय करें और छात्रों को सीख भी दी कि मोबाइल की आदत विकसित न करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित भारत 2047' के संकल्प में राष्ट्रहित



प्रथम का भाव हृदय में रखते हुए विद्यार्थियों को भावी नागरिक के रूप में अपना दायित्व निभाने का अनुरोध करने के लिए शुरू किया गया 'परीक्षा पे चर्चा' का यह नूतन दृष्टिकोण अब बच्चों के लिए एक प्रेरणात्मक कार्यक्रम बन गया है।

मुख्यमंत्री ने गौरवपूर्वक उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष परीक्षा से पहले बच्चों के बीच जाकर 'परीक्षा पे चर्चा' के अंतर्गत प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देने वाले संभवतः विश्व के एकमात्र नेता होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा-2026' के समारोह के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों में संस्कार, समझ और सदाचार, इन तीन 'S' का निर्माण हो, इसके लिए 'परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम' की शुरुआत की थी। विद्यार्थियों के कौशल को प्रोत्साहित करने के साथ प्रधानमंत्री से सीधे संवाद से विद्यार्थी चिंतामुक्त, दबाव से बाहर रहकर पढ़ाई को अपनाने लगे हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी जोड़ा कि शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा नहीं है। शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है, इसलिए परीक्षा अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नैतिकता की स्थापना एवं चेतना के साथ विद्यार्थियों में सकारात्मक विचार उत्पन्न हों, इसके लिए 'परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम' को माध्यम बनाया है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और विद्यार्थियों से परीक्षा को आनंदपूर्वक एक अवसर के रूप में लेने का अनुरोध किया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मिलिंद तोरवणे, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम. ए. पंड्या, कलेक्टर श्री मेहुल दवे, जिला विकास अधिकारी श्री बी. जे. पटेल, आनंद निकेतन स्कूल के डस्ट्री श्री विवेकभाई पटेल तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित रहे।

## मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने छारी-ढंड को मिले वैश्विक 'रामसर साइट' दर्ज का प्रशस्ति पत्र अर्पित किया

गुजरात का पांचवां तथा कच्छ का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण वेटलैंड बना 'छारी-ढंड'  
(जीएनएस)। गांधीनगर : कच्छ के बन्नी का रत्न छारी-ढंड को आधिकारिक रूप से 'रामसर साइट' घोषित किया गया है। छारी-ढंड को मिले इस वैश्विक 'रामसर साइट' के दर्ज का प्रशस्ति पत्र शुरुआत को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को वन और पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने वन विभाग की ओर से अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने गुजरात की इस उपलब्धि के लिए मंत्री सहित वन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी।  
उल्लेखनीय है कि छारी-ढंड गुजरात का पांचवां और कच्छ का पहला अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण वेटलैंड बना है। गुजरात राज्य के लिए गर्व की बात है कि कच्छ जिले में स्थित 'छारी ढंड पक्षी अभयारण्य' को अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड्स की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। इसके साथ ही गुजरात में रामसर साइट्स की संख्या अब बढ़कर पांच हो गई है।



मुख्यमंत्री ने गुजरात की इस उपलब्धि के लिए मंत्री सहित वन विभाग की पूरी टीम को बधाई दी।

## लाखाबावल एवं पीपली स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के ठहराव अस्थायी रूप से रद्द

(जीएनएस)। राजकोट मंडल के अंतर्गत लाखाबावल एवं पीपली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) के निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के ठहराव (स्टॉपेज) को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। लाखाबावल स्टेशन पर यह व्यवस्था 25 फरवरी, 2026 तक तथा पीपली स्टेशन पर 25 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। संबंधित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—



ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर-ट्रेना-भावनगर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 25.02.2026 तक लाखाबावल स्टेशन पर ठहराव अस्थायी रूप से रद्द।

ट्रेन संख्या 19210 ओखा-भावनगर एक्सप्रेस तत्काल प्रभाव से 25.03.2026 तक पीपली स्टेशन पर ठहराव अस्थायी रूप से रद्द। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि उपरोक्त अस्थायी फेरबदल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ट्रेनों के परिचालन से संबंधित नवीनतम एवं अद्यतन जानकारी के लिए यात्री कृपया [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर अवलोकन करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से

## पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार, 8 फरवरी 2026 को सांताक्रुज एवं गोरेगांव के बीच जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेक, सिग्नलिंग तथा ओवरहेड उपकरणों के अनुरक्षण कार्य हेतु रविवार, 08 फरवरी 2026 को सांताक्रुज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइन पर 10:00 बजे से 15:00 बजे तक पाँच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान सभी स्लो लाइन की लोकल ट्रेनें सांताक्रुज एवं गोरेगांव के बीच फास्ट लाइनों पर चलाई जाएँगी। इसके कारण प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण ये ट्रेनें विले पालें एवं राम मंदिर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। हालाँकि, विले पालें और राम मंदिर स्टेशनों पर हावर लाइन (चचेगेट-गोरेगांव सेवाएँ) उपलब्ध रहेगी। इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएँ निरस्त रहेगी, जबकि कुछ बोरिवली एवं अंधेरी सेवाएँ हावर लाइन के माध्यम से गोरेगांव तक चलाई जाएँगी। प्रभावित ट्रेनों की विस्तृत सूची उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें तथा तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

## अहमदाबाद मंडल का जनवरी 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन - यात्री सुविधा, सुरक्षा एवं राजस्व वृद्धि के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध

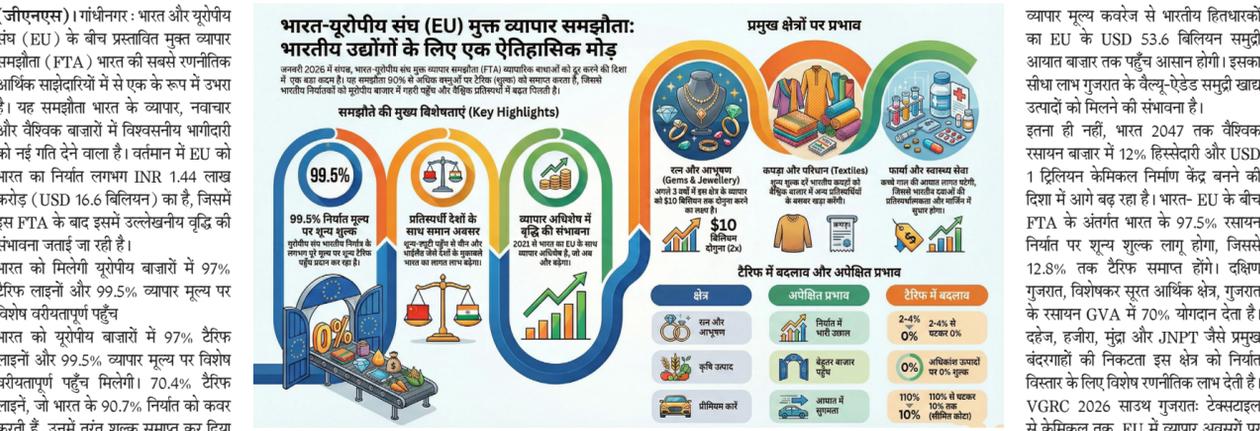
जनवरी 2026 में 800 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित कर बनाया कीर्तिमान  
(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल यात्रियों को सुखित, सुगम एवं बेहतर सेवाएँ प्रदान करने तथा राजस्व वृद्धि के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जनवरी 2026 के दौरान मंडल ने यात्री एवं माल राजस्व, टिकट जांच, गैर-भाड़ा राजस्व तथा व्यवसाय विकास के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।  
राजस्व एवं यात्री उपलब्धियाँ  
अहमदाबाद मंडल ने जनवरी 2026 में कुल 806.86 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.43% अधिक है।  
▶▶ 150.57 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है।  
▶▶ 642.29 करोड़ का माल राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष से 18% अधिक है।  
▶▶ जनवरी 2026 में 33.80 लाख यात्रियों को परिवहन सेवा प्रदान की गई, जो पिछले वर्ष से 9.28% अधिक है।  
▶▶ टिकट जांच अभियानों से 2.25 करोड़ की आय अर्जित हुई, जो पिछले वर्ष से 26.40% अधिक है।  
▶▶ सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियाँ (Best Ever)  
▶▶ कंटेनर कमांडिटी से 215.73 करोड़ का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मासिक माल राजस्व प्राप्त हुआ, जो दिसंबर 2025 के 211.45 करोड़ से अधिक है।  
▶▶ IFFCO साइडिंग, खोडियार से 9.44 करोड़ का सर्वश्रेष्ठ मासिक राजस्व अर्जित हुआ, जो अक्टूबर 2025 के 9.21 करोड़ से अधिक है।  
▶▶ LPG साइडिंग से 12.92 करोड़ का सर्वश्रेष्ठ राजस्व प्राप्त हुआ तथा LPG



कमांडिटी ने भी नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया, जो दिसंबर 2025 के 10.73 करोड़ से अधिक है।  
▶▶ सामाखियाली फ्रेट टर्मिनल से 8.32 करोड़ का सर्वश्रेष्ठ मासिक राजस्व प्राप्त हुआ।  
▶▶ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2,700 मामलों से 5.05 लाख की रिकॉर्ड जुमाना वसूली की गई।  
▶▶ 12.07 करोड़ का गैर-भाड़ा राजस्व अर्जित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।  
▶▶ प्रतीक्षासूची यात्रियों की सुविधा हेतु 32 विशेष ट्रेन ट्रिप चलाई गईं, जिनसे 5.92 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।  
▶▶ पार्सल एवं लीजिंग  
▶▶ ई-नीलामी के माध्यम से तीन पार्सल परिसंपत्तियों के लिए तीन वर्ष की लीज प्रदान कर 7.96 करोड़ का राजस्व सुनिश्चित किया गया।  
▶▶ ओवरलॉडिंग के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाते हुए चार एम्पलआर में आकस्मिक जांच की गईं, जिसमें 15.21 विवटल

## VGRC 2026 साउथ गुजरात बनेगा भारत-EU FTA से खुलने जा रहे व्यापार अवसरों का बड़ा मंच

▶▶ भारत को मिलेगी यूरोपीय बाजारों में 97% टैरिफ लाइनों और 99.5% व्यापार मूल्य पर विशेष वरीयतापूर्ण पहुँच  
▶▶ EU का USD 263.5 बिलियन का टेक्सटाइल मार्केट और USD 79.2 बिलियन का जेम्स एन्ड ज्वेलरी मार्केट सूरत के लिए बनेगा बड़ा अवसर  
▶▶ VGRC 2026 साउथ गुजरात: टेक्सटाइल से केमिकल तक, EU में व्यापार अवसरों पर रहेगा विशेष फोकस



(जीएनएस)। गांधीनगर : भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की सबसे रणनीतिक आर्थिक साझेदारियों में से एक के रूप में उभरा है। यह समझौता भारत के व्यापार, नवाचार और वैश्विक बाजारों में विश्वसनीय भागीदारी को नई गति देने वाला है। वर्तमान में EU को भारत का निर्यात लगभग INR 1.44 लाख करोड़ (USD 16.6 बिलियन) का है, जिसमें इस FTA के बाद इस्में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। भारत को मिलेगी यूरोपीय बाजारों में 97% टैरिफ लाइनों और 99.5% व्यापार मूल्य पर विशेष वरीयतापूर्ण पहुँच

भारत को यूरोपीय बाजारों में 97% टैरिफ लाइनों और 99.5% व्यापार मूल्य पर विशेष वरीयतापूर्ण पहुँच मिलेगी। 70.4% टैरिफ लाइनें, जो भारत के 90.7% निर्यात को कवर करती हैं, उनमें तुरंत शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इनमें वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, चार्ज, कॉफी, मसाले, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ओटोमोबाइल, इस्पात, दवाइयों और रसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुजरात से EU को हुए कुल निर्यात में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 25% रही है। EU का USD 263.5 बिलियन का टेक्सटाइल मार्केट और USD 79.2 बिलियन का जेम्स & ज्वेलरी मार्केट सूरत के लिए बनेगा बड़ा अवसर

हिससेदारी है। गुजरात का सूरत, जो MMF और सिंथेटिक वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, इस नए अवसर से सबसे अधिक लाभ उठाने की स्थिति में है। इसी तरह, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, खासकर MSME आधारित इकाइयों, EU बाजार में नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने जा रही है। सूरत, जो विश्व के सबसे बड़े हीरा प्रसंस्करण केंद्रों में से एक है, 5,000 से अधिक इकाइयों का प्रमुख हब है। EU के USD 79.2 बिलियन के आयात बाजार तक विशेष पहुँच भारत के USD 2.7 बिलियन

आभूषण निर्यात को नई गति दे सकती है। साथ ही, सूरत SEZ में 250 से अधिक इकाइयों आभूषण, हीरा और वस्त्र क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो इन नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। भारत-EU के बीच FTA से गुजरात के वैल्यू-एडेड समुद्री खाद्य उत्पाद और केमिकल इन्डस्ट्री का भी होगा विस्तार भारत-EU के बीच FTA लागू होने के बाद समुद्री निर्यात क्षेत्र भी बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्तमान में EU को भारत का समुद्री निर्यात USD 1 बिलियन है। FTA के बाद 26% तक टैरिफ में कमी और 100%

व्यापार मूल्य कवरेज से भारतीय हितधारकों का EU के USD 53.6 बिलियन समुद्री आयात बाजार तक पहुँच आसान होगा। इस्का सीधा लाभ गुजरात के वैल्यू-एडेड समुद्री खाद्य उत्पादों को निर्यात की संभावना है। इतना ही नहीं, भारत 2047 तक वैश्विक रसायन बाजार में 12% हिस्सेदारी और USD 1 ट्रिलियन केमिकल निर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत-EU के बीच FTA के अंतर्गत भारत के 97.5% रसायन निर्यात पर शून्य शुल्क लागू होगा, जिससे 12.8% तक टैरिफ समाप्त होंगे। दक्षिण गुजरात, विशेषकर सूरत आर्थिक क्षेत्र, गुजरात के रसायन GVA में 70% योगदान देता है। दहेज, हजीरा, मुंद्रा और JNPT जैसे प्रमुख बंदरगाहों की निचटला इस क्षेत्र को निर्यात विस्तार के लिए विशेष रणनीतिक लाभ देती है। VGRC 2026 साउथ गुजरात: टेक्सटाइल से केमिकल तक, EU में व्यापार अवसरों पर रहेगा विशेष फोकस अप्रैल 2026 में सूरत में आयोजित होने वाला वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट (VGRC) दक्षिण गुजरात उद्योगों के लिए FTA से खुले अवसरों को व्यापारिक रूप देने का मंच बनेगा। वस्त्र, रत्न-आभूषण, रसायन-पेट्रोकेमिकल और समुद्री उत्पाद जैसे उच्च-विकास सेक्टर EU की बढ़ती मांग से सीधे जुड़े हैं। 99.5% व्यापार मूल्य पर टैरिफ समाप्ति के साथ, यह समवेत क्षेत्रीय उद्योगों को निर्यात वृद्धि की दिशा में ठोस और समर्थित कदम उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

## पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस-अजमेर तथा वलसाड-हिसार के बीच चल रही तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:  
1. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल



के फेरे को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल के फेरे को 28 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।  
2. ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर साप्ताहिक स्पेशल के फेरे को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09621 अजमेर - बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल के फेरे को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।  
3. ट्रेन संख्या 04728/04727 वलसाड - हिसार साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 04728 वलसाड - हिसार साप्ताहिक स्पेशल के फेरे को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार - वलसाड टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल के फेरे को 25 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 04828, 09622 एवं 04728 के विस्तारित फेरे की बुकिंग 08.02.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय-सारणी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर अवलोकन कर सकते हैं।

## अखिल भारतीय अंतर रेलवे सांस्कृतिक संगीत प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे ओवरऑल चैंपियन बना

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर गौरव प्राप्त करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर रेलवे सांस्कृतिक संगीत प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन ट्रांफ़ी अपने नाम की है। यह दो दिवसीय प्रतियोगिता 2 एवं 3 फरवरी 2026 को आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए प्रतिभाशाली रेलवे कर्मचारियों ने अपनी सीमित प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, भारतीय रेल प्रसंस्करण केंद्रों में से एक है, कुल 147 प्रतिभागियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रतियोगिता में पश्चिम रेलवे सहित 14



मुख्यालय, चचेगेट की श्रीमती प्रेरणा बाजे ने सुगम संगीत गायन श्रेणी में तृतीय स्थान हासिल किया। वाद्य संगीत श्रेणी में रत्नाम मंडल के श्री दिनेश भंबरिया तथा मुख्यालय के श्री संतोष चावमारे ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दीं।

उन्हें श्री कपिल देव, श्री आदित्य मालवीय एवं श्री दिनकर भागत का सलतक सहयोग प्राप्त हुआ, जिनकी उल्लेखनीय संगत ने पश्चिम रेलवे की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के परिणामस्वरूप पश्चिम रेलवे ने ओवरऑल चैंपियन ट्रांफ़ी गर्व के साथ अपनी नाम की, जो इसके कर्मचारियों में निहित समृद्ध सांस्कृतिक प्रतिभा को दर्शाता है।